भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 2413

सोमवार, 10 अगस्त, 2026 (19 श्रावण, 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान-1 योजना की उपलब्धियां

2413. श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकियाः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) उड़ान-1 योजना की उपलब्धियां क्या हैं;
(ख) उड़ान-1 योजना के अंतर्गत वर्तमान में गैर-प्रचालनरत मार्गों तथा विमानपत्तनों के संबंध में सामने आई समस्याएं तथा चुनौतियां क्या हैं और इनके समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) उड़ान-1 योजना के अंतर्गत वर्तमान में गैर-प्रचालनरत विमानपत्तनों तथा मार्गों के प्रचालन हेतु सरकार की क्या योजना है; और
(घ) वर्ष 2026-27 के दौरान उड़ान-2 योजना के अंतर्गत देशभर में विकसित किए जाने हेतु प्रस्तावित हेलीपैडों तथा विमानपत्तनों की संख्या कितनी है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): दिनांक 10.07.2026 तक, उड़ान योजना के तहत देश भर में 17 हेलीपोर्ट और 02 वॉटर एयरोड्रोम सहित 95 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले कुल 679 आरसीएस मार्गों को प्रचालनरत किया गया है, जिससे 3.58 लाख से अधिक आरसीएस उड़ानों के माध्यम से 168 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ हुआ है।

इस योजना ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क में काफी सुधार किया है, दूरस्थ और अल्पसेवित क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाई है, पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा दिया है और नागरिकों को किफायती हवाई यात्रा प्रदान की है।

(ख) और (ग): उड़ान योजना के तहत जो मार्ग और हवाईअड्डे वर्तमान में प्रचालन में नहीं हैं, वे मार्ग की आर्थिक और परिचालन व्यवहार्यता जैसे कारकों और अन्य संबंधित कारकों के कारण प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा, तीन वर्ष की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ)

अवधि की समाप्ति, खराब दृश्यता की स्थिति, विमानों की कमी, पट्टे से संबंधित मुद्दे और कम यात्री भार जैसे कारकों के कारण भी इन्हें बंद करना पड़ा।

योग्य गैर-प्रचालनरत मार्गों को उड़ान योजना के बाद के चरणों में पुन: बोली लगाने के लिए उपलब्ध कराया जाता है ताकि मौजूदा मांग और परिचालन व्यवहार्यता के आधार पर नए एयरलाइन प्रचालकों का चयन सुविधाजनक हो सके। इसके अलावा, उड़ान योजना के अगले चरण में पांच वर्ष तक का विस्तारित वीजीएफ तंत्र शामिल किया गया है, जिसे उत्तरोत्तर कम किया जाएगा ताकि एयरलाइनें व्यावसायिक रूप से संधारणीय परिचालन की ओर अग्रसर हो सकें।

(घ): सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक दस वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 04.07.2026 को 28,840 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ उड़ान योजना का अगला चरण शुरू किया है, जिसमें 12,159 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मौजूदा असेवित हवाईपट्टियों से 100 हवाईअड्डों का विकास और पर्वतीय, पूर्वोत्तर और आकांक्षी (एचआईएनईआर) क्षेत्रों में 200 हेलीपोर्ट के विकास के लिए 3,661 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल हैं।

******